के. जनार्दन

बनाम

यूनाईटेड़ इंडिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड़ व अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 5831/2002)

9 मई, 2008

(तरूण चटर्जी और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

श्रमिक मुआवजा अधिनियम-धारा 2(1) (ई)- मुआवजा - पीड़ित को उस काम के लिए अक्षम करने की जिसे वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था- अपीलकर्ता - टैंकर चालक, दुर्घटना का शिकार हुआ-उसका दाहिना पैर घुटने से कट गया - दुर्घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र 30 वर्ष थी और वह प्रति माह 2000/- रुपये कमाता था - मुआवजे के लिए दावा- माना गयाः अपीलकर्ता को 100 प्रतिशत विकलांगता का सामना करना पड़ा और वह अपनी आय अर्जित करने में असमर्थ था एक टैंकर चालक के रूप में वह ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से भी अयोग्य हो गया- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कामगार मुआवजा आयुक्त ने अपीलकर्ता को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2.5 लाख रुपये का मुआवजा दुर्घटना की तारीख से निर्धारित करने में सही निर्णय लिया (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एसएस 8 और 9)

अपीलकर्ता, एक टैंकर चालक, अपना वाहन चलाते समय विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को गंभीर चोटे आईं और उसका दाहिना पैर घुटने के जोड़ तक कट गया। इसके बाद उन्होंने कामगार मुआवजा आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर कर मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये देने की प्रार्थना की। आयुक्त ने देखा कि दावेदार की उम्र 30 वर्ष थी और उसका वेतन 2000/-प्रति माह निर्धारित किया। आयुक्त ने यह भी पाया कि चूंकि दावेदार का दाहिना

पैर घुटने तक कट गया था, इसलिए उसे ड्राइवर के रूप में अपनी कमाई क्षमता का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ था और तदनुसार उसके लिए मुआवजा 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2.50 लाख रू. दुर्घटना की तारीख से निर्धारित किया। इसके बाद प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने अपील में उठाई गई दलील को स्वीकार कर लिया कि श्रमिक मुआवजा अधिनियम की अनुसूची के अनुसार, विच्छेदन पर एक पैर का नुकसान कमाई क्षमता में 60 प्रतिशत की कमी है और जैसा कि डॉक्टर ने 65 प्रतिशत विकलांगता की राय दी थी, इस आंकड़े को स्वीकार किया जाना था और तदनुसार मुआवजे को घटाकर लगभग 1.62 लाख रूपये कर दिया गया।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि वह एक टैंकर चालक है, उसके दाहिने पैर की क्षति का मतलब वास्तव में पूरी तरह से विकलांगता है, जैसा कि श्रमिक मुआवजे की धारा 2(1)(ई) के संदर्भ में समझा जाता है। अधिनियम और उस आधार पर अपने मुआवजे की गणना करने का हकदार था।

अपील को स्वीकार करते हुए,

निर्धारित: 1. अपीलकर्ता को 100 प्रतिशत विकलांगता का सामना करना पड़ा और टैंकर चालक के रूप में अपनी नौकरी अर्जित करने में असमर्थता हुई क्योंकि उसका दाहिना पैर घुटने से कट गया था। इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 8 और 9 का एक अवलोकन यह दिखाएगा कि अपीलकर्ता अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी अयोग्य होगा। (पैरा 5) (161-सी,डी)

1.2. उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया है और आयुक्त के फैसले को बहाल कर दिया गया है। (पैरा 6) (161-डी)

प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबटा और अन्य सबटा (1976) 1 एससीसी 289- पर आधारित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 5831/2002

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एमएफए संख्या 484/2000 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 6.10.2001 से।

अपीलकर्ता की ओर से आर.एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश, अश्वनी गर्ग और पी.पी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय हरजीत सिंह बेदी, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील निर्देशित हैः- कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के 6 अक्टूबर, 2001 के फैसले और आदेश के खिलाफ, जिसके तहत कर्मकार मुआवजा आयुक्त द्वारा दिए गए 2,49,576/- रूपये के मुआवजे को घटाकर 1,62,224.40/- रूपये कर दिया गया है। यह निम्नलिखित तथ्यों से उत्पन्न होता है।

2. दावेदार-अपीलकर्ता एक टैंकर चालक है, जो अयानूर से शिमोगा की ओर अपना वाहन चला रहा था और विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रैक्टर के साथ उसकी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को गंभीर चोटे आईं और उसका दाहिना पैर घुटने के जोड़ तक कट गया। इसके बाद उन्होंने कामगार मुआवजा आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर कर प्रार्थना की कि चूंकि वह 25 वर्ष का है और 3,000/- रूपये प्रति माह रुपये कमाता है। और 100 प्रतिशत विकलांगता का सामना करने पर, वह मुआवजे की 5 लाख रुपये की राशि का हकदार था। आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 18 नवंबर, 1999 में पाया कि दावेदार की उम्र 30 वर्ष थी और उसके द्वारा दावा किया गया वेतन अधिक था और तदनुसार उसे रूपये 2000/- प्रति माह निर्धारित किया गया। आयुक्त ने यह भी पाया कि चूंकि दावेदार का दाहिना पैर घुटने तक कट गया था, इसलिए कहा गया कि उसे ड्राइवर के रूप में अपनी कमाई क्षमता का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ था और तदनुसार उसे देय मुआवजा रुपये निर्धारित किया गया था। 2,49,576/- और ब्याज 12 प्रतिशत प्रति वर्ष दुर्घटना की तारीख से इसके बाद बीमा

कंपनी-प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने अपील में उठाई गई दलील को स्वीकार कर लिया कि श्रमिक मुआवजा अधिनियम की अनुसूची के अनुसार, विच्छेदन पर एक पैर का नुकसान कमाई क्षमता में 60 प्रतिशत की कमी है और जैसा कि डॉक्टर ने 65 प्रतिशत विकलांगता की राय दी थी, इस आंकड़े को स्वीकार किया जाना था और तदनुसार मुआवजे को कम किया जाना था जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है। इसी परिस्थिति में पीड़ित दावेदार इस अदालत में आया है

3. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील ने सुनवाई के दौरान केवल एक ही तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि दावेदार-अपीलकर्ता एक टैंकर चालक है, उसके दाहिने पैर की क्षति का मतलब वास्तव में पूरी तरह से विकलांगता है जैसा कि नीचे दिया गया है। कामगार मुआवज़ा अधिनियम की धारा 2(1)(ई) की शर्तें और इस तरह अपीलकर्ता अपना हक पाने का हकदार था। मुआवजे की गणना उस आधार पर की जाती है। इस दलील के समर्थन में, विद्वान वकील ने प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबटा और अन्य (1976) 1 एससीसी 289 पर भरोसा जताया है। उद्धृत मामला एक बढ़ई से संबंधित है, जिसका बायाँ हाथ कोहनी से कट गया था और यह अदालत ने माना कि यह पूरी तरह से विकलांगता की श्रेणी में आता है क्योंकि चोट ऐसी प्रकृति की थी कि दावेदार उन सभी कार्यों से अक्षम हो गया था जो वह कर रहा था। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसका अवलोकन किया गया।

4. अभिव्यक्ति "पूर्ण विकलांगता" को अधिनियम की धारा 2(1)(ई) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

> "(1) 'पूर्ण विकलांगता का अर्थ ऐसी विकलांगता है, चाहे वह अस्थायी या स्थायी प्रकृति की हो, जो श्रमिक को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम कर देती है, जिन्हें वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी विकलांगता हुई"

हमारे समक्ष इस बात पर कोई विवाद नहीं हुआ है कि चोट ऐसी प्रकृति की थी कि जिससे प्रतिवादी स्थायी रूप से विकलांग हो गया, और विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विकलांगता ने प्रतिवादी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम कर दिया, जिन्हें घटना के समय करने में सक्षम था। दुर्घटना आयुक्त ने प्रश्न की जांच की और अपना निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किया हैः

> "इस मामले में घायल कामगार पेशे से बढ़ई है... कोहनी के ऊपर बायां हाथ खोने के कारण, वह स्पष्ट रूप से बढ़ई के काम के लिए अयोग्य हो गया है क्योंकि बढ़ईगीरी का काम केवल एक हाथ से नहीं किया जा सकता है"

यह स्पष्टतः एक उचित एवं सही तर्क है। अपीलकर्ता के वकील किसी भी आधार पर इसे खारिज करने में सक्षम नहीं हैं और इस अपील में इसे सही करने की आवश्यकता नहीं है। अनुसूची 1 के भाग II के आईटम 3 के संदर्भ में दिए गए अन्य तर्क का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह आयुक्त के समक्ष अपीलकर्ता का मामला नहीं था कि हाथ का विच्छेदन 8 इंच से एक्रोमियन की नोक से कम तक हुआ था। ओलेक्रानोन की नोक से 4 नीचे। इसलिए उन तथ्यों पर एक नया मामला स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है या स्थापित नहीं किया गया है।

5. उद्धृत निर्णय के अनुपात को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर हमारी राय है कि अपीलकर्ता को भी 100 प्रतिशत विकलांगता का सामना करना पड़ा है और एक टैंकर चालक के रूप में अपनी आजीविका अर्जित करने में असमर्थता हुई है क्योंकि उसका दाहिना पैर कट गया था। घुटना इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 8 और 9 के अवलोकन से पता चलेगा कि अपीलकर्ता ड्राइविंग लाइसेंस पाने से भी अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है?

6. इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करते हैं और आयुक्त के फैसले को यथावत बहाल करते हैं, लेकिन वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी धर्मराज मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।